रेलवे की नई पॉलिसी, यात्रा के दौरान खाने का बिल नहीं तो फ्री में खाएं भोजन

नई दिल्ली,एजेन्सी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई योजनाओं की शुरूआत की है जिससे रेलवे यात्रियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिल रहा है। न सिर्फ ट्रेनों की लेट-लतीफी की समस्या को खत्म करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है बल्कि टिकट आरक्षण में आने वाली समस्याओं को सुलझाने का रेलवे भरपूर प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी कुछ समय पहले ही रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलने वाले खाने के सामान के वास्तविक मूल्य की सूची जारी की थी जिससे लोगों को ठगी का शिकार होने से बचने का फायदा मिला।रेलवे लाया नई पॉलिसीअब रेलवे एक नई पॉलिसी लेकर आया है जिसका नाम है- 'नो बिल, फ्री फूड पॉलिसी'। रेलवे ने इस पॉलिसी को लांच किया है जिसका मतलब है खाने का बिल नहीं तो पैसा नहीं यानी ट्रेन में अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अगर आपको भोजन का बिल नहीं मिला तो खाने का पैसा नहीं लगेगा और ऐसे में आप फ्री में खाना खा सकते हैं। यह नई पॉलिसी इंडियन रेलवे द्वारा इस वजह से लाई गई है क्योंकि रेलवे में कई बार भोजन खरीदने पर बिल नहीं दिया जाता है।नई योजना के मुताबिक रेलवे ने कहा है कि यात्री अब खाना लेने के बाद इसका बिल मांगें और अगर कोई वैंडर बिल देने से मना करता है तो खाने के पैसे न दें। इस नई पॉलिसी के नोटिस को उन सभी ट्रेनों में लगाए जाने का विचार किया जा रहा है जिन ट्रेनों में यात्री यात्रा के दौरान खाना खरीदते हैं। यह नई योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं इसके लिए रेलवे इंस्पैक्टरों को नियुक्त करेगा जो इस बात की निगरानी करेंगे कि यात्रियों से तय दाम के मुताबिक पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं और इसका सही-सही बिल दिया जा रहा है या नहीं।

जून में दो साल के उच्चतम स्तर पर रह सकती है खुदरा महंगाई : रॉयटर्स पोल

नई दिल्ली (ए)। जून महीने के दौरान खुदरा महंगाई दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। रॉयटर्स का एक पोल बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को मौद्रिक नीति को और सख्त करने पर मजबूर कर सकता है।4 से 9 जुलाई के दौरान करीब 37 अर्थशास्त्रियों के बीच हुए सर्वे के मुताबिक पिछले महीने खुदरा महंगाई दर 5.30 फीसद के स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि जुलाई 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है। मई महीने में खुदरा महंगाई 4.87 फीसद रही थी और यह भी आरबीआई के महंगाई लक्ष्य 4 फीसद के मुकाबले लगातार आठवें महीने ज्यादा रही है। उस डेटा के बारे में जिसे 12 जुलाई को शाम 5 बजकर 30 मिनट पर जारी किया जाना है के 4.60 से 6 फीसद के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। जून में उच्च महंगाई दर आरबीआई की ओर से अगस्त में नीतिगत ब्याज दरों में इजाफे की संभावना को जोर दे सकती है। आरबीआई ने पिछली बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया। कैपिटल इकोनॉमिक्स के सीनियर इंडिया इकोनॉमिस्ट शिलान शाह ने बताया, साप्ताहिक डेटा बताता है कि फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन दोनों में इजाफा हो सकता है। हम पिछले महीने खुदरा महंगाई में और इजाफे को देख रहे हैं।शाह ने आगे बताया कि उन्हें कोर मुद्रास्फीति को ऊंचा बने रहने की उम्मीद हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती तेल की कीमतें जो कि इस साल 20 फीसद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, (जिसमें से अकेले 13 फीसद जून महीने में) बीते कुछ महीनों के दौरान महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रही है। क्योंकि इससे भारत का आयात महंगा हो जाता है।

अमेरिका ने लगाया 200 अरब डॉलर के चीनी आयात पर टैरिफ

नई दिल्ली (ए)। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार को लेकर तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका की ओर से हालिया फैसले में ट्रंप ने 200 अरब डॉलर के चीनी आयात पर 10 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा की है।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि वॉशिंटन में आधी रात के बाद से चीन के सामान पर ये टैरिफ लागू हो जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि बीते वर्ष ट्रंप ने 34 अरब डॉलर के चीनी आयात पर 25 फीसद टैरिफ लगाया गया था। इसपर जवाबी पलटवार करते हुए चीन ने कहा है कि वह भी अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाएगा।इससे पहले ट्रंप ने मीडिया को बताया था कि कुल टैरिफ 550 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यह वर्ष 2017 में चीन से किये गये अमेरिकी सामान के कुल आयात से कई ज्यादा है। अमेरिका के कस्टम अधिकारी चीन के आयात पर 25 फीसद का अतिरिक्त टैरिफ वसूलेंगे। इस सामान में कृषि उपकरण से लेकर सेमीकंडक्टर्स और एयरप्लेन के पार्ट्स शामिल हैं। चीनी अधिकारियों ने पहले बताया था कि वे इसका जवाब अमेरिकी सोयाबीवन से लेकर पोर्क तक पर उच्च टैरिफ लगाएगा। चीन का यह फैसला ट्रंप को उच्च ट्रेड बैरियर के लिए मजबूर कर सकता है।बता दें कि चीन के वाणिज्य मंत्री ने एक बयान में कहा था कि अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन किया है और आर्थिक इतिहास में अबतक की सबसे बड़ी ट्रेड वार को छेड़ दिया है।

अब 2 नहीं, 3 दिन चलेगी मौद्रिक नीति समिति की बैठक

नई दिल्ली (ए)। प्रमुख नीतिगत दर पर निर्णय करने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक अब तीन दिन चला करेगी। रिजर्व बैंक ने तीन दिवसीय बैठक के प्रारूप को जारी रखने का निर्णय किया है। एमपीसी प्रमुख नीतिगत दर पर निर्णय करती है।रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक दो दिन की होती रही है। लेकिन पिछली बार कुछ 'प्रशासनित जरूरतों' के कारण बैठक तीन दिन तक चली। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि एमपीसी ने आगे से तीन दिवसीय बैठक के प्रारूप को जारी रखने का फैसला किया है। एमपीसी की गत छह जून 2018 को घोषित चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक तीन दिन चली थी। इसी तरह अगली बैठक 30 जुलाई 2018 को शुरू होगी।पहले तय कार्यक्रम के अनुसार एमपीसी की दो दिवसीय बैठक 31 जुलाई को शुरू होनी थी तथा एक अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की जानी थी। रिजर्व बैंक ने यह नहीं बताया है कि किन कारणों से यह बैठक दो दिन की जगह तीन करने का निर्णय किया गया है।

फ्लिपकार्ट, एमेजॉन के दबदबे में कमी चाहती हैं छोटी ई-कॉमर्स कंपनियां

नई दिल्ली,एजेन्सी। ई-कॉमर्स में फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट रूल्स लागू करवाने के लिए प्रेस नोट 3 का इस्तेमाल करने के सरकार के फैसले का स्नैपडील और शॉपक्लूज जैसी छोटी ई-कॉमर्स कंपनियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे मार्केटप्लेस और सेलर्स के लिए बराबरी का प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा। इससे कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से प्रॉक्सी सेलर्स के लिए की जा रही गलत गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी।

देश की टॉप ई-कॉमर्स कंपनियों एमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर सेलर्स और कुछ अन्य पक्षों ने प्रेस नोट 3 के तहत नॉर्म्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। प्रेस नोट के तहत एक सेलर को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर कुल बिक्री का 25 पर्सेंट से अधिक बेचने की अनुमति नहीं है। देश के ऑनलाइन रिटेल सेगमेंट में फ्लिपकार्ट और एमेजॉन की संयुक्त रूप से 70 पर्सेंट से अधिक हिस्सेदारी है।

इन दोनों कंपनियों ने ईटी की ओर से भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ईटी ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी थी कि ई-कॉमर्स सेक्टर में विदेशी निवेश से संबंधित प्रेस नोट 3 को लागू करने के लिए सरकार ने एक अलग विंग बनाने का फैसला किया है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी शामिल होंगे।

सरकार ई-कॉमर्स सेक्टर में स्वछ्ठ, ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से एकत्र किए गए डेटा के उद्देश्य और इस्तेमाल, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और अन्य मामलों से निपटने के लिए एक रेगुलेटर बनाने पर भी विचार कर रही है। स्नैपडील और शॉपक्लूज जैसी कंपनियां ई-कॉमर्स सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। 2017 में स्नैपडील का मार्केटशेयर केवल

2.5 पर्सेंट और शॉपक्लूज का 2.1 पर्सेंट था। इसके मुकाबले में फ्लिपकार्ट के पास 39.5 पर्सेंट और एमेजॉन के पास 31.1 पर्सेंट मार्केटशेयर था।

स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा, देश में डिजिटल कॉमर्स की यात्रा में मार्केटप्लेस का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ कंपनियां इस मॉडल का गलत इस्तेमाल कर रिटेलर बन रही हैं और छोटे रिटेलर्स को मार्केट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के एक एग्जिक्यूटिव के अनुसार, छोटे सेलर्स के लिए कारोबार की समान स्थितियां होने से ग्रोथ संतुलित होगी और यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल कॉमर्स के फायदे कुछ मार्केटप्लेस की ओर से बनाए गए प्रॉक्सी सेलर्स तक ही नहीं, बल्कि लाखों वास्तविक सेलर्स तक पहुंचें। सेलर्स एसोसिएशंस और ई-कॉमर्स से जुड़े अन्य पक्ष ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े क्लाउडटेल जैसे सेलर्स को फायदा पहुंचाने की शिकायतें करते रहे हैं। क्लाउडटेल का मालिकाना हक एमेजॉन और देश की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के फैमिली ऑफिस कैटामारन वेंचर्स के संयुक्त उपक्रम के पास है। एमेजॉन पर 2014 से क्लाउडटेल बड़े सेलर्स में शामिल है।

21000 करोड़ रुपए में एयरबस और बोइंग के 19 विमान खरीदेगी विस्तार

दिल्ली,एजेन्सी । टाटा समूह की विमाननकंपनीविस्तार एयरलाइंस ने कुल 19 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। इसमें 3.1 अरब डॉलर यानी 21,344 करोड़ रुपए में एयरबस और बोइंग दोनों के विमान खरीदे जाने हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि अपना परिचालन विस्तार करने और विदेशी उड़ान सेवा शुरू करने के लिए वह इन विमानों का उपयोग करेगी। बयान के अनुसार विस्तार ने एयरबस से 13 ए-320 नियो विमान और बोइंग से छह 787-9 ड्रीमलाइनर विमान की खरीद का ऑर्डर दिया है। इस सौदे की कीमत 3.1 अरब डॉलर है। वर्तमान में कंपनी के पास ए-320 नियो के 21 विमानों का बेड़ा है। कंपनी की योजना ऐसे अन्य 50 विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की है।

विस्तारा ने ए320 नियो और ए321 नियो एयरक्राफ्ट के लिए सीएफएम इंटरनेशनल के लीप 1-ए इंजन को चुना है। इन एयरक्राफ्ट की आपूर्ति 2019 से 2023 के बीच की जाएगी। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल घरेलू नेटवर्क को मजबूत बनाने और इस साल के अंत से अंतरराष्ट्रीय परिचालन में मदद के

आचार्य बालकृष्ण बोले, रुचि सोया को खरीदने की दौड़ से नहीं हटेंगे पीछे

नई दिल्ली (ए)। पतंजलि आयुर्वेद, दिवालियापन का सामना कर रही रुची सोया हासिल करने की दौड़ से पीछे नहीं हटेगी और वह इसकी खरीद को लेकर कानूनी समेत सभी विकल्पों की तलाश कर रही है। यह जानकारी पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने दी है।

फॉर्च्यून ब्रांड के अंतर्गत कुकिंग ऑयल बेचने वाली अडाणी विल्मर और बाबा रामदेव की पतंजलि कर्ज में डूबी रुचि सोया को खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। 6 हजार करोड़ रुपए के साथ अडाणी सबसे बड़े बोलीदाता के रुप में उभरा था, जबकि पतंजलि ने लगभग 5,700 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी।अडाणी विल्मर के एच1 के तौर पर उभरने के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने बोली प्रक्रिया (बिडिंग प्रोसेस) में भाग लेने के लिए अडाणी ग्रुप की पात्रता के संबंध में रुचि सोया के रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) से स्पष्टीकरण मांगा था। पतंजलि ने अडाणी विल्मर को सबसे बड़ा बोलीदाता घोषित करने के लिए आरपी की ओर से अपनाए गए पैरामीटर्स की जानकारी मांगी थी।

हरिद्वार स्थित कंपनी ने आरपी के लीगल एडवाइजर के तौर पर सिरिल अमरचंद मंगलदास की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि लॉ कंपनी पहले से ही अडाणी ग्रुप को सलाह दे रही थी। एक कार्यक्रम के दौरान आचार्य बालकृष्ण ने कहा, हम अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

अब भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फ्रांस को पछाड़ा : वर्ल्ड बैंक

नई दिल्ली (ए)। फ्रांस को पीछे छोड़ भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी वर्ल्ड बैंक की ओर से 2017 के लिए जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार सामने आई है। वर्ष 2017 के अंत तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.597 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर रहा है, जबकि फ्रांस का 2.582 ट्रिलियन डॉलर रहा है।

कई तिमाहियों तक मंदी से गुजरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में जुलाई 2017 से मजूबत सुधार देखने को मिला है। भारत की कुल आबादी 1.34 बिलियन है। भारत

दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने की कगार पर है। वहीं फ्रांस की आबादी 67 मिलियन है।बीते वर्ष विनिर्माण और उपभोक्ता खर्च देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले मुख्य कारक रहे हैं। इससे पहले नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद से इसमें मंदी देखने को मिली थी। एक दशक में भारत की जीडीपी दोगुना हो गई है और भविष्य में इसकी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार इस साल देश की ग्रोथ 7.4 फीसद और वर्ष 2019 में 7.8 फीसद रहने का अनुमान है। इसे घर खर्च और कराधान से बूस्ट मिलेगा।

लंदन आधारित सेंटर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने कहा था कि बीते वर्ष के अंत तक भारत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ देगा और वर्ष 2032 तक उसके पास दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अवसर है।वर्ष 2017 के अंत तक ब्रिटेन 2.622 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है।

भूषण पावर के सप्लायर्स ने सरकार से बकाया पैसा दिलाने को कहा

मुंबई दिल्ली,एजेन्सी। भूषण पावर एंड स्टील के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने कंपनी पर अपनी बकाया रकम दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। इन सप्लायर्स का कहना है कि अगर उन्हें अपनी रकम नहीं मिलती तो उन्हें अपनी यूनिट्स बंद करनी पड़ सकती हैं।

बैंकरप्ट हो चुकी भूषण पावर एंड स्टील के सप्लायर्स के एक ग्रुप ने पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर पेमेंट दिलवाने में मदद करने का निवेदन किया है। प्रधान ओडिशा से संबंध रखते हैं और भूषण स्टील एंड पावर का इसी राज्य में प्लांट है। कंपनी के लेंडर्स की ओर से स्वीकृत रिजॉल्यूशन प्लान में सप्लायर्स (जिन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कहा जाता है) की बकाया रकम शामिल नहीं है।एक सप्लायर ने बताया, हमें अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बैड लोन बचाने के लिए बैंकर्स 1,500 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं।

भूषण पावर एंड स्टील पर लगभग 1,700 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के करीब 723 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा कंपनी को 1,200 अन्यों के भी लगभग 600 करोड़ रुपये चुकाने हैं। इनमें से अधिकतर की बकाया रकम 10-50 लाख रुपये के बीच है, जबकि केवल 149 क्रेडिटर्स को 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक की रकम लेनी है।

भूषण पावर एंड स्टील के लेंडर्स ने कंपनी के लिए टाटा स्टील की बिड स्वीकार की है। क्रेडिटर्स ने बताया कि के रिजॉल्यूशन प्लान में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और सरकार की बकाया रकम को मिला दिया गया है और इसके बदले में 100 करोड़ रुपये देने पर सहमति दी है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और सरकार की कंपनी पर बकाया रकम लगभग 1,480 करोड़ रुपये है और टाटा स्टील इसमें से केवल 7 पर्सेंट ही चुकाएगी।

बहुत से ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने भुगतान के लिए सप्लायर्स के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि भूषण पावर एंड स्टील के प्रमोटर्स से जुड़े कुछ लोगों की कंपनियों को अन्य सप्लायर्स के मुकाबले अधिक भुगतान किया जा रहा है। इस बारे में कंपनी के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुछ क्रेडिटर्स के क्लेम इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान घट गए थे क्योंकि कुछ पोस्ट-डेटेड चेकों के जरिए भुगतान हुआ था। लेकिन इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड नियमों में इनसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होने के बाद क्रेडिटर्स को कोई भुगतान करने पर रोक लगाई गई है। भूषण पावर एंड स्टील के लेंडर्स ने सोमवार को टाटा स्टील के रिजॉल्यूशन प्लान को स्वीकृति दे दी थी।

लेंडर्स ने ब्रिटेन की लिबर्टी हाउस और भूषण पावर एंड स्टील के प्रमोटर्स दोनों की बिड अस्वीकार कर दी थी। टाटा स्टील ने कंपनी के लिए 17,500 करोड़ रुपये की बिड दी थी। लिबर्टी हाउस की 18,500 करोड़ रुपये की बिड इससे अधिक होने के बावजूद लेंडर्स ने टाटा स्टील को मजबूत वित्तीय ताकत के कारण चुना था।

जीरो बजट प्राकृतिक खेती से लाभप्रद बनेगी कृषिः नायडू

नई दिल्ली,एजेन्सी। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेती को सतत और लाभप्रद बनाने के लिए शून्य लागत वाली प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि लागत में कटौती होने से किसानों की आय बढ़ेगी। नायडू ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर और आंध प्रदेश सरकार के कृषि सलाहकार विजय कुमार के साथ परिचर्चा के दौरान यह कहा। यह परिचर्चा किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी परिचर्चाओं और सलाह-मशविरों का हिस्सा है। बातचीत के दौरान देवव्रत ने उप राष्ट्रपति को हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढाने के लिए अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों की जानकारी दी।

कुमार और पालेकर ने लागत में कटौती करने और प्राकृतिक

खेती को बढावा देने में शून्य बजट कृषि की भूमिका की जानकारी दी। नायडू ने कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और हाल में महाराष्ट्र के पुणे में कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चा के नतीजों पर भी बात की। उन्होंने खेती को लाभकारी बनाने के लिए नवाचारी समाधानों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने लागत में बढोतरी और किसानों की आय में कमी पर चिंता व्यक्त की और साथ ही खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेज वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की।

आंध्र प्रदेश टॉप पर, दिल्ली में बिजनेस हुआ पहले से मुश्किल

नई दिल्ली,एजेन्सी। देश में कारोबार करने में सुगमता के लिहाज से आंध्रप्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है। औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की गई रैंकिंग में आंध्र प्रदेश अव्वल रहा है। वहीं दिल्ली में बिजनेस करने पहले से मुश्किल हो गया है। दिल्ली 2016 में 19वें पायदान पर था जो अब खिसक कर 23वें पायदान पर आ गया है।

एक नजर अन्य राज्यों की रैंकिंग पर: डीआईपीपी के इस संबंध में जारी बयान के मुताबिक तेलंगाना और हरियाणा इस मामले में क्रमश = दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष दस में झारखंड चौथे स्थान पर, गुजरात पांचवे, छत्तीसगढ़ छठे, मध्य प्रदेश सातवें, कर्नाटक आठवें, राजस्थान नौवें पर और

पश्चिम बंगाल दसवें स्थान पर रहा। सूची में मेघालय आखिरी 36 वें स्थान पर रहा।

कैसे होती है रैंकिंग: डीआईपीपी, विश्वबैंक के साथ मिलकर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता के आधार पर रैंकिंग करता है।

डीआईपीपी कारोबारी क्षेत्र में और सुधार लाने के लिये कारोबार सुधार कार्ययोजना (ब्रैप) के तहत यह करता है। बयान के अनुसार, ''ब्रैप 2017 में सुझाए गए कई सुझावों पर बड़ी संख्या में राज्यों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।'' ब्रैप 2017 के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त अंक प्रदान किए गए। इन संयुक्त अंकों का आधार दो तरह के अंक 'सुधार साक्ष्य अंक' और 'प्रतिपुष्टि अंक' हैं। सुधार साक्ष्य अंक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों पर आधारित हैं, जबकि प्रतिपुष्टि अंक कारोबारियों को दी जाने वाली सेवाओं के वास्तविक उपयोक्ताओं से जुटाई गई प्रतिक्रिया के आधार पर तय किए गए हैं। डीआईपीपी के अनुसार, 17 राज्यों का सुधार साक्ष्य अंक ब्यौरा 90त से अधिक रहा है, जबकि संयुक्त अंक में 15 राज्यों को 90त से अधिक अंक मिले हैं। जिन राज्यों का सुधार साक्ष्य अंक 80त से अधिक रहा हैं'।

आसान नहीं है माल्या की संपत्ति जब्त करना, बैंकों की बढ़ेगी मुश्किल

नई दिल्ली (ए)। भारतीय बैंकों से करोड़ों का कर्ज लेकर देश से फरार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश हाई कोर्ट ने इंग्लैंड और वेल्स में संपत्तियां जब्त करने का आदेश तो दे दिया लेकिन माल्या के किसी भी घर पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी गई। कोर्ट ने सिर्फ माल्या के घरों में मौजूद उससे जुड़े सामानों को जब्त करने का आदेश दिया है।

नहीं पता माल्या के पास कितनी संपत्ति

यूके में माल्या के पास कुल कितनी संपत्ति है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। माल्या के घर उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हैं और फैमिली ट्रस्ट के नाम पर ज्यादातर संपत्तियां होने से भारतीय एजेंसियों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि वे कर्ज की वसूली कैसे करेंगी। कोर्ट ने 8 मई को बेंगलुरू डीआरटी के फैसले में ब्रिटेन की ईडी को माल्या की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दी थी। हालांकि माल्या ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसके पास कुछ कारों और जेवरात के अलावा ब्रिटेन में कुछ खास संपत्ति नहीं है। उसने कहा था कि उसके टेविन एस्टेट पर उसके बच्चों का मालिकाना हक है और लंदन स्थित उसके घर पर उसकी मां का।

संपत्ति जब्त करना होगा मुश्किल

ब्रिटेन स्थित माल्या के तीनों घर उसके फैमिली ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। फैमिली ट्रस्ट के नाम से संपत्तियों के होने का माल्या को फायदा पहुंच सकता है क्योंकि जब तक उसकी संपत्तियां ट्रस्ट के नाम रहेंगी, तब तक उनकी जब्ती बहुत ही मुश्किल होगी। बैंकों ने हाई कोर्ट को बताया है कि माल्या के पास इंग्लैंड में जो संपत्तियां हैं, उनमें उसके शानदार कारों का बेड़ा भी शामिल है।